[श्रीमती मनोरमा डी. शर्मा]
अनुमान है। इस परियोजना के निर्माण के उपरांत सौंग नदी पर लगभग 5 किलोमीटर लम्बी झील का निर्माण होगा और लगभग 65 हेक्टेयर भूमि डूब क्षेत्र में आयेगी। संयोग से इस डूब क्षेत्र में कोई आबादी नहीं है। इस झील के पानी का सिंचाई हेतु भी उपयोग हो सकेगा।

प्रस्तावित बांध के लिए विस्तृत अनुसंधान कार्य शुरू हो चुका है और भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग की संस्तुति पर शुरू किये गये इस अनुसंधान एवं सर्वेक्षण का लगभग 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इस बांध के बनने से कम से कम 2051 तक पेयजल समस्या से पूर्ण रूप से मुक्ति मिलने के साथ ही प्रदेश को इससे 6 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। अनुसंधान कार्य पूर्ण होने पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर केन्द्रीय जल आयोग को स्वीकृति हेतु भेजी जायेगी।

मेरा आपके माध्यम से संबंधित विभाग के मंत्री जी से अनुरोध है कि इस बहुउद्देशीय बांध के निर्माण में राज्य सरकार का सहयोग करने की कृपा करें, ताकि राजधानी देहरादून की पेयजल समस्या का निराकरण हो सके।

श्रीमती कहकशां परवीन (बिहार) **:** महोदय, मैं स्वयं को इस विशेष उल्लेख से सम्बद्ध करती हूं।

चौधरी मुनव्वर सलीम (उत्तर प्रदेश) **:** महोदय, मैं स्वयं को इस विशेष उल्लेख से सम्बद्ध करता हूं।

[†چودھری منوّر سلیم (اتر پردیش) : مہودے، میں خود کو اس وشیش الیکھ سے سمبدھ کرتا]

श्री अरविंद कुमार सिंह (उत्तर प्रदेश) **:** महोदय, मैं भी स्वयं को इस विशेष उल्लेख से सम्बद्ध करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Shri Mahendra Singh Mahra; absent. Now, Shri Dilip Kumar Tirkey.

Need to open a Central Tribal University in Odisha and making arrangements to give Free Higher Education to Tribal Children

श्री दिलीप कुमार तिर्की (ओडिशा) **:** महोदय, ओडिशा में देश की कुल ट्राइबल आबादी का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा रहता है। ट्राइबल लोगों की संख्या ओडिशा की कुल आबादी में 22 प्रतिशत से ज्यादा है, मगर उनकी शिक्षा की दशा आज की बेहाल है। दसवीं और बारहवीं तक तो फिर भी आश्रम स्कूलों के माध्यम से गरीब और साधनहीन ट्राइबल बच्चों को शिक्षा मिल जाती है, मगर उनकी हायर एजुकेशन का कोई इंतजाम नहीं है। ऐसे में टैलेंटेड ट्राइबल बच्चे आश्रम स्कूलों से निकलने के बाद वापस गांव लौट जाते हैं। हायर एजुकेशन बिना उन्हें ढंग की कोई नौकरी भी नहीं मिलती। इसलिए, मेरी सरकार से यह मांग है कि ओडिशा में भी एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोली जाये और ट्राइबल बच्चें की फ्री हायर एजुकेशन का इंतजाम किया जाये।

---

†Transliteration in Urdu Script.

महोदय, ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चें न सिर्फ फिजिकल और मेंटल लेवल पर स्ट्राँग होते हैं, बल्कि ट्राइबल कल्चर भी बहुत रिच है। इसको बचाने और आगे बढ़ाने के लिए ओडिशा में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना बहुत जरूरी है। इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी में स्किल डेवलपमेंट और स्पोर्ट्स फैकल्टी पर भी पूरा जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ट्राइबल बच्चे पारम्परिक रूप से खेल के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इससे वेलफेयर के साथ-साथ देश में स्पोर्ट्स के फील्ड में टैलेंट तैयार करने का काम भी हो जायेगा। इसके अलावा, मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह भी मांग है कि अभी जो आश्रम स्कूल्स हैं, वहां भी पढ़ाई के साथ-साथ वोकेशनल एजुकेशन के कोर्सेज़ शुरू किये जायें और आश्रम स्कूलों में भी ग्रेजुएशन लेवल तक की पढ़ाई शुरू की जाये, ताकि आश्रम स्कूलों से निकलने वाले बच्चे कम-से-कम बेरोज़गार न रहें। धन्यवाद।

श्री भूपिंदर सिंह (ओडिशा) **:** महोदय, मैं स्वयं को इस विशेष उल्लेख से सम्बद्ध करता हूं।

श्रीमती कहकशां परवीन (बिहार) **:** महोदय, मैं स्वयं को इस विशेष उल्लेख से सम्बद्ध करती हूं।

चौधरी मुनव्वर सलीम (उत्तर प्रदेश) **:** महोदय, मैं भी स्वयं को इस विशेष उल्लेख से सम्बद्ध करता हूं।

†[چودھری منوّر سلیم (اتر پردیش) : مہودے، میں بھی خود کو اس وشیش الیکھ سے سمبدھ کرتا ہوں۔]

श्री अरविंद कुमार सिंह (उत्तर प्रदेश) **:** महोदय, मैं भी स्वयं को इस विशेष उल्लेख से सम्बद्ध करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Dr. T.N. Seema; absent. Shri Bhupinder Singh.

Need to give Special Category status to the State of Odisha

SHRI BHUPINDER SINGH (Odisha): Sir, the demand of Odisha for getting a Special Category Status is very old and fully justified. Our demand was made in 1979 in the National Development Council. That effort continued in 1990s when both the Tenth and the Eleventh Odisha Legislative Assemblies adopted unanimous Resolutions urging upon the Government of India to declare Odisha as a Special Category State. Our hon. Chief Minister, since 2001, has been vigorously pursuing with the Government of India for according Special Category Status to Odisha. He had requested the then hon. Prime Ministers on 31st May, 2001, and on 22nd July, 2004, and on 24th November, 2011. Our State Government also submitted a memorandum in this regard to the then hon.

†Transliteration in Urdu Script.